

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 860
जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

.....

जलाशयों में भंडारण की स्थिति की निगरानी

860. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री डी एन वी सेंथिलकुमार एस :

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री बी मणिकम टैगोर:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश के जलाशयों में भंडारण की स्थिति की निगरानी करती है और यदि हां, तो विशेष रूप से तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने घोषणा की है कि 2019 की तुलना में जलाशयों में 155 प्रतिशत अधिक जल मौजूद है;
- (ग) यदि हां, तो सभी राज्यों में सबसे अधिक जल-भंडार वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने मानसून की वर्षा पर निर्भरता घटाने के लिए जलाशयों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार का देश में नए जलाशय निर्मित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा देश में भू-जल स्तर में सुधार हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर 171.090 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) संचयी क्षमता वाले 123 जलाशयों के सक्रिय स्टोरेज स्टेटस की देख रेख करता है, जो 257.812 बीसीएम का 66.36% है जो देश में सृजित कुल अनुमानित स्टोरेज क्षमता थी। तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार वर्तमान टस, तुलनात्मक स्थिति तथा न्य विवरण यूआरएल <http://www.cwc.gov.in/reservoirs-storage-bulletin> पर उपलब्ध हैं। रिजर्वॉयर (जलाशय) स्टोरेज बुलेटिन दिनांकित 10.09.2020 के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय संग्रह 142.234

बीसीएम है। तमिलनाडु में मॉनीटर किए जा रहे 6 जलाशयों में कुल उपलब्ध सक्रिय संग्रह दिनांक 10.09.2020 के बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों की कुल सक्रिय संग्रह क्षमता का 71% है।

(ख) साप्ताहिक बुलेटिन में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) गतवर्ष के उपलब्ध सक्रिय संग्रह के साथ समतुल्य अवधि हेतु तथा विगत 10 वर्षों के सक्रिय संग्रह के औसत सहित 123 जलाशयों के वर्तमान सक्रिय संग्रह की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करता है। सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी साप्ताहिक बुलेटिन के अनुसार, जनवरी 2020 से अब तक 16.01.2020 से 13.02.2020, 27.02.2020 से 09.07.2020 तक तथा 23.07.2020 को 2019 की तुलना में वर्तमान वर्ष का संग्रह प्रतिशत 155% हो गया है।

(ग) सीडब्ल्यूसी बुलेटिन के अनुसार मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना तथा हिमाचल प्रदेश 25.06.2020 तक सर्वोच्च सक्रियसंग्रह वाले राज्य हैं।

(घ)और(ङ) जल राज्य का विषय होने के नाते : ज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी जलाशयों की संग्रह क्षमता को बढ़ाना है चाहे अपने संबंधित राज्यों में नई संग्रह संरचनाओं का निर्माण करके या विद्यमान संग्रह की क्षमता में वृद्धि करके। भारत सरकार की भूमिका जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समय-समय पर जब-जब राज्यों द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर परियोजनाओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना होता है।

(च) जुलाई 2019 के दौरान जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन की सुविधा प्रदान करने के लिए नागरिक सहभागिता के संबंध में निर्मित जल संरक्षण अभियान को प्रोत्साहित करने, परम्परागत जल निकायों के नवीकरण, जलभृत विकास, वनीकरण और देश के 256 जिलों में सूखा प्रभावित, जल की कमी वाले या अति दोहित लगभग 1500 ब्लॉकों में जन जागरूकता सृजित करने के लिए मिशन मोड में एक गहन समयबद्ध कार्यक्रम जल शक्ति अभियान आरंभ किया। इसके अतिरिक्त, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जल की कमी वाली 8353 ग्राम पंचायतों में स्थाई भूजल प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने के लिए विश्व बैंक से एक ऋण सहायता स्कीम, अटल भूजल योजना आरंभ की जा रही है।
